मासिक

केवलारी (सिवनी)

जनवरी 2026

हिन्द शिला

पंजीकरण संख्या MPBIL/25/A1756

खबर वही ,जो हो सच

» वर्ष : 3 » अंक : 33 » पृष्ठ : 04 » मुल्य : 3 रूपये

तकनीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि

भारत में 3D-प्रिंट स्वचालित मौसम स्टेशन का निर्माण शुरू

ये स्टेशन देशभर में मौसम की निगरानी को मजबूत करेंगे

नई दिल्ली » हिन्द शिला

तकनीकी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए, भारतीय वैज्ञानिकों ने 3डी-प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके स्वदेशी रूप से निर्मित स्वचालित मौसम स्टेशन (AWS) विकसित करना शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य देश भर में अंतिम छोर तक मौसम संबंधी निगरानी को मजबूत करना है। अगली पीढ़ी के इन स्टेशनों का पहला बैच फरवरी से राष्ट्रीय राजधानी में स्थापित किया जाएगा। न्यूज 18 रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने भारत की मौसम की जानकारी और भविष्यवाणी को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ी योजना शुरू की है। यह 'मिशन मौसम' नाम की योजना है, जिस पर 2,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस योजना का नेतृत्व पुणे का भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) कर रहा है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन ने कहा कि हमारा उद्देश्य अवलोकन नेटवर्क का इतना व्यापक विस्तार करना है कि डेटा की कमियां दूर हो जाएं। तापमान, हवा, आर्द्रता और वर्षा जैसे मापदंडों को अधिक स्थानों पर दर्ज करने से स्थानीय स्तर पर अधिक सटीक पूर्वानुमान संभव हो सकेंगे। हम दिल्ली जैसे बड़े शहरों से शुरुआत करेंगे और ये स्टेशन सौर ऊर्जा से संचालित होंगे।

पहले बड़े शहरों पर फोकस

मौसम मिशन के तहत, अवलोकन संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, खासकर शहरी मौसम विज्ञान के क्षेत्र में। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में अगले छह महीनों में स्वचालित मौसम प्रणाली (AWS) और रडार प्रतिष्ठानों का तेजी से विस्तार होने की उम्मीद है।

कैसे काम करेगा 3D स्वचालित मौसम स्टेशन

पारंपरिक मौसम वेधशालाओं के मुकाबले एडब्ल्यूएस मौसम का डेटा अपने आप मापते और भेजते हैं। इससे चलाने का खर्च काफी कम हो जाता है। लेकिन, जानकार लोग इस बात पर ज़ोर देते हैं कि इन मशीनों को ठीक से कैलिब्रेट करना और उनका रखरखाव करना बहुत ज़रुरी है। इस साल की शुरुआत में सटीकता का महत्व तब और भी साफ हो गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के कुछ एडब्ल्यूएस ने बहुत ज़्यादा तापमान दिखाया। बाद में पता चला कि या तो उनके सेंसर खराब थे या फिर वे ऐसी जगह पर लगे थे जहाँ की परिस्थितियां सही नहीं थीं।

समय-सीमा तभी तय करें जब जांच में देरी हो

सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों के लिए क्यों कही ये बड़ी बात

नई दिल्ली » हिन्द शिला

सुप्रीम कोर्ट ने मामलों की जांच करने के लिए अदालतों की तरफ से एजेंसियों के लिए समय सीमा निर्धारित करने को लेकर अहम बात कही है। शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि एक जांच एजेंसी को जांच करने की आजादी मिलनी चाहिए। शीर्ष अदालतने साफ कहा कि अदालतों को आम तौर पर एजेंसियों के लिए जांच पूरी करने की समय-सीमा तय करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह 'बाद वाले के काम में दखल देने' जैसा होगा। जस्टिस संजय करोल और एन के सिंह की बेंच ने कहा कि अदालतें समय-सीमा तभी तय करें जब एजेंसी जांच पूरी करने में देरी कर रही हो। उन्होंने कहा कि संक्षेप में, समय-सीमा प्रतिक्रिया के तौर पर लगाई जाती है, न कि पहले से ही। इसके साथ ही उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें राज्य पुलिस को जाली दस्तावेजों के आधार पर हथियारों के लाइसेंस हासिल करने से जुड़े एक आपराधिक मामले में जांच पूरी करने के लिए 90 दिन की समय-सीमा तय की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टाइमलाइन तय करने वाले न्यायिक निर्देश तभी जरूरी होते हैं, जब साफ तौर पर काम रुका हुआ हो। अदालत ने कहा कि बिना किसी वजह के कार्रवाई न हो रही हो या देरी का ऐसा पैटर्न हो जिसे किसी केस की प्रकृति या जटिलता से सही नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के अलग-अलग फैसलों का जिक्र करते हुए बेंच ने कहा कि इस चर्चा से यह जरूरी नतीजा निकलता है कि जांचकर्ताओं/ कार्यकारियों द्वारा शुरू से ही पालन करने के लिए कोर्ट टाइमलाइन तय नहीं करता है, क्योंकि ऐसा करना साफ तौर पर बाद वालों के काम में दखल देना होगा।

ममता सरकार में मां, माटी, मानुष असुरक्षित: शाह

कहा- दिल पर लिख लो, इस बार भाजपा सरकार

कोलकाता » हिन्द शिला

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कोलकाता में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक की। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से चुनाव में जीत का लक्ष्य तय करने को कहा। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शाह ने कहा- ममता सरकार ने 'मां, माटी, मानुष' का नारा दिया था, लेकिन आज उनके कार्यकाल में सुरक्षित नहीं है। शाह ने कहा- बंगाल में महिलाएं असुरक्षित हैं, जमीन पर माफियाओं का कब्जा है और लोग पलायन को मजबूर हैं। शाह ने कहा कि घुसपैठिए न सिर्फ अर्थव्यवस्था पर बोझ हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और बंगाल की सांस्कृतिक पहचान के लिए भी खतरा हैं।

शाह ने कहा- ममता सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं, जिनमें शिक्षक भर्ती घोटाला, SSC घोटाला, नगर निगम भर्ती घोटाला, कोयला घोटाला, राशन घोटाला, एमजीएनआरईजीए घोटाला और पीएम आवास योजना घोटाला शामिल हैं।

गृह मंत्री ने कहा- 2016 से 2025 के बीच भाजपा के 300 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। अपने 42 सालों के सार्वजनिक जीवन में मैंने ऐसा बलिदान और समर्पण कभी नहीं देखा। अब समय आ गया है कि उन

बलिदानों का फल दिया जाए। दिल पर लिख लो, इस बार हमारी सरकार।

शाह बोले- कोलकाता और आसपास की 28 में से 22 सीटें जीतने का लक्ष्य : शाह ने कोलकाता और आसपास के इलाकों से 28 में से 22 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा। कोलकाता और उससे सटे शहरी इलाकों में जादवपुर, दमदम और मध्य कोलकाता की जोरासांको, श्यामपुकुर जैसी सीटें शामिल हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा यहां एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। अपने करीब एक घंटे के भाषण में शाह ने भवानीपुर सीट का भी जिक्र किया, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2021 का उपचुनाव जीता था।

मुंह से आ रही थी शराब की बू, उड़ान से पहले कनाडा में पकड़ा गया एयर इंडिया पायलट

कनाडा » हिन्द शिला

कनाडा के वैंकूवर एयरपोर्ट पर क्रिसमस के फेस्टिव सीजन का माहौल एक एयर इंडिया पायलट के लिए महंगा साबित हो गया। पायलट को शराब की तेज बू आने के कारण दिल्ली के लिए उड़ान भरने से पहले हिरासत में ले लिया गया। यह फ्लाइट एआई 186 वैंकूवर से दिल्ली के लिए थी, जो वियना के रास्ते जाने वाली थी। यह अल्ट्रा लॉन्ग हॉल फ्लाइट चार पायलटों की टीम द्वारा संचालित की जानी थी। मामला 23 दिसंबर 2025 का है। हालांकि बोइंग 777 विमान के इस पायलट को उड़ान से ठीक पहले ड्यूटी से हटा दिया गया क्योंकि कनाडाई अधिकारियों ने उन्हें ब्रेथ एनालाइजर (बीए) टेस्ट में फेल पाया। जानकारी के अनुसार, वैंकूवर एयरपोर्ट के ड्यूटी-फ्री स्टोर पर एक स्टाफ सदस्य ने या तो पायलट को गलती से वाइन की चुस्की लेते हुए देख लिया- जो फेस्टिव सीजन में चखने के लिए ऑफर की जा रही थी या फिर शराब खरीदते वक्त उनके मुंह से शराब की गंध महसूस की। इसी आधार पर मामले की सूचना कनाडाई अधिकारियों को दी गई।

ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए प्लान तैयार

ईरान के कुछ हिस्सों में सत्ताविरोधी प्रदर्शन तेज हो चुके हैं

नई दिल्ली » एजेंसी

ईरान के कुछ हिस्सों में सत्ताविरोधी प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। छह दिन से चल रहे प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में अब तक कम से कम सात लोग मारे जा चुके हैं। ये प्रदर्शन आंशिक रूप से ईरान की रियाल मुद्रा के पतन के कारण भड़के थे, लेकिन यह अब तेजी से सत्ताविरोधी प्रदर्शन का रूप लेती जा रही है। इस बीच जेनजी प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी से यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में मदद की भी बात कही है। प्रदर्शन के बीच भारत का कहना है कि अगर ईरान में स्थिति बिगड़ती है तो वह अपने नागरिकों को निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

विरोध पर क्या कह रहा भारत?

भारत ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से शासन के खिलाफ कार्रवाई की धमकियों पर कड़ी नजर रख रहा है। भारत का कहना है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो अपने नागरिकों को निकालने के लिए तैयार है। तेहरान में किसी भी विदेशी मिशन ने अब तक कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है।

कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा

लोकतंत्र की कीमत पर विकास नहीं हो सकता

नई दिल्ली » हिन्द शिला

मोदी सरकार देश में बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में देरी को दूर करने में जुटी है। इस तरह की बड़े प्रोजेक्ट्स में जमीन अधिग्रहण, और जंगल और वन्यजीवों से जुड़ी मंजूरियों में समय लगता है। ऐसे में PM मोदी के नेतृत्व वाले बड़े प्रोजेक्ट्स के प्लेटफॉर्म प्रगति ने इस तरह की परेशानियों को दूर करने की दिशा में अहम काम किया है। इस मुद्दे पर कैबिनेट सचिव टी वी सोमनाथन ने शुक्रवार को यह साफ कर दिया कि विकास लोकतंत्र की कीमत पर नहीं हो सकता है।मौजूदा पॉलिसी में बदलाव के बारे में पूछे जाने पर सोमनाथन ने कहा कि लोकतंत्र में हमें संतुलन बनाना होता है... हम लोगों की सहमति से और पब्लिक कंसल्टेशन के बाद प्रोजेक्ट्स को लागू करना चाहते हैं। यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब बिजनेस कम्युनिटी के एक वर्ग की ओर से प्रोजेक्ट्स को तेजी से लागू करने के लिए भूमि अधिग्रहण पॉलिसी की समीक्षा करने की मांग की जा रही है। इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के चीनी मॉडल का हवाला देता है। हालांकि बीजेपी सरकार ने अपने पहले

कार्यकाल में भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने राज्यों पर एक आसान व्यवस्था देने की ज़िम्मेदारी छोड़ दी थी। एक सवाल के जवाब में, कैबिनेट सचिव टी वी सोमनाथन ने कहा कि सरकार की अपनी भूमि अधिग्रहण नीति में बदलाव करने की कोई योजना नहीं है। सोमनाथन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर किए गए डेटा से पता चला कि मल्टी-लेयर प्रगति के तहत उठाए गए 7,735 मुद्दों में से 35% भूमि अधिग्रहण से संबंधित थे, इसके बाद 20% वन्यजीव और वन मंजूरी से संबंधित थे।

कैबिनेट सचिवालय में समन्वय सचिव मनोज गोविल ने कहा कि वन और वन्यजीव मंजूरी के लिए लगने वाला औसत समय 600 दिनों से घटकर लगभग 75 दिन हो गया है, क्योंकि प्रगति से मिली सीख प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बन गई है। PM ने 50 मीटिंग्स में 382 प्रोजेक्ट्स का रिव्यू किया। इनमें से लगभग दो-तिहाई जमीन और जंगल से जुड़े थे। सेक्टर्स में, सड़कें सबसे ऊपर थीं (114 प्रोजेक्ट्स), उसके बाद रेलवे (109) और पावर (54) थे। रेलवे और सड़कों के लिए, कम से कम आधे मुद्दे जमीन अधिग्रहण से जुड़े हैं।

85 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सोमनथन ने कहा कि अब तक PM के नेतृत्व वाले पैनल ने 85 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, क्योंकि राज्यों और केंद्र ने मिलकर मुद्दों को हल करने के लिए काम किया है। जम्मू-उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक का उदाहरण देते हुए, देश के सबसे बड़े सिविल सर्वेंट ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को 1994 में मंज़ूरी मिली थी। जब यह 2015 में प्रगति के तहत आया, तब तक सिर्फ 40% काम हुआ था। उच्चतम स्तर पर निगरानी के बाद पिछले जून में इसे आखिरकार चालू किया गया। उन्होंने कहा कि अगर यह प्रोजेक्ट प्रगति के तहत नहीं लिया जाता, तो यह जनवरी 2038 तक ही पूरा होता।

गगनयान का पहला बिना क्रू वाला मिशन कब तक लॉन्च होने की संभावना है?

मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान की समयसीमा फिर बदली

नई दिल्ली » हिन्द शिला

भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान की समयसीमा एक बार फिर बदल गई है। संशोधित डेडलाइन के बावजूद अब तक पहली बिना चालक (अनक्रूड) उड़ान नहीं हो सकी है। अब नई समयरेखा के मुताबिक, गगनयान की पहली अनक्रूड मिशन HLVM3 G1/ OM1 के इस साल मार्च से पहले लॉन्च होने की संभावना जताई जा रही है। इस मिशन में बिना दाब वाला यानी अनप्रेसराइज्ड क्रू मॉड्यूल इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मकसद पूरे मिशन प्रोफाइल का प्रदर्शन करना है- मानव-रेटेड लॉन्च व्हीकल के जरिए अंतरिक्ष यान को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना, क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित री-एंट्री, समुद्र में सफल स्प्लैशडाउन और मॉड्यूल की रिकवरी।

गगनयान मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में लाल किले से की थी। तब लक्ष्य 2021 रखा गया था, जब भारत आजादी के 75 साल मना रहा था। लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान सप्लाई चेन और निर्माण से जुड़ी चुनौतियों के कारण मिशन में देरी हुई। इसके बाद तय की गई कई समयसीमाएं भी पूरी नहीं हो सकीं। वित्त वर्ष 2022 में इसरो ने अगले साल कम से कम एक मिशन का वादा किया। फिर वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 24 के लिए लक्ष्य शून्य कर दिया गया। वित्त वर्ष 25 में दो मिशनों की बात कही गई। ताजा वार्षिक रिपोर्ट में वित्त वर्ष 26 में तीन मिशनों का लक्ष्य रखा गया है, जो फिलहाल मुश्किल नजर आता है।

लॉन्च की तैयारी और सिस्टम टेस्ट

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इसरो ने दिसंबर 2024 में गगनयान के लिए 'ऑफिशियल लॉन्च कैंपेन'शुरु किया। इसमें 18 दिसंबर 2024 से रॉकेट के पहले चरण के सॉलिड मोटर की असेंबली शुरु हुई। क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल के एकीकरण का काम भी शुरु हो चुका है। जनवरी 2025 तक क्रू मॉड्यूल में प्रोपल्शन सिस्टम और अन्य अहम सिस्टम जोड़कर आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा गया। हालांकि मिशन अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन कई अहम सिस्टम्स का परीक्षण पूरा हो चुका है। क्रू एस्केप सिस्टम के हाई एल्टीट्यूड, लो एल्टीट्यूड और जेटिसनिंग मोटर्स की टेस्टिंग हो चुकी है।

नए नियम

सीएनजी और पीएनजी 2 सस्ती हुई, नए साल से लागू हुए नए बदलाव

कॉमर्शियल सिलेंडर हुआ 111 रुपए महंगा, कारों के दाम भी बढ़े

नई दिल्ली » हिन्द शिला

आज यानी 1 जनवरी 2026 से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 111 रुपए बढ़ गए हैं। वहीं कार खरीदने के लिए भी आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी। केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने का भी ऐलान किया है। अभी टाइमलाइन नहीं बताई गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यह जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। कुल मिलाकर इस महीने 6 ऐसे बड़े बदलाव हो रहे हैं जिनका असर हमारी जिंदगी पर पड़ेगा... आज से 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 111 रुपए तक महंगा हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 111 रुपए बढ़कर 1691.50 हो गई है। पहले यह 1580.50 में मिल रहा था। वहीं मुंबई में यह अब 111 रुपए महंगा होकर 1642.50 रुपए में मिलेगा। घरेलू सिलेंडर के दामों में बदलाव नहीं किया गया है।

12 जनवरी से दिन में रेलवे रिजर्वेशन के लिए आधार जरुरी

12 जनवरी से ऐसे यूजर्स जिनका अपना आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, वे सुबह 8 से रात 12 बजे तक टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। यह नियम केवल रिजर्व टिकट बुकिंग खुलने के पहले दिन के लिए हैं। रिजर्वेशन के लिए ट्रेन डिपार्चर की तारीख से 60 दिन पहले खुलती है। जिस दिन ये बुकिंग खुलती है इसे पहला दिन माना जाता है। इसका मकसद ओपनिंग डे पर ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स को ऑनलाइन टिकट बुक करने का मौका देना है और फर्जी अकाउंट्स के जरिए होने वाली बुकिंग को रोकना है।

हुंडई, एमजी, निसान जैसी कंपनियों की कारें महंगी : जनवरी 2026 से कई कार कंपनियों ने भारत में

अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। इसमें हुंडई, MG, निसान जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से इनपुट कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स खर्च और करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से है। ज्यादातर बढ़ोतरी 2-3% तक है।

मर्सिडीज-बेंज: सभी मॉडल्स के दाम 2% तक बढ़े।

निसान इंडिया: मैग्नाइट और अन्य कारों की कीमतों में 3% तक का इजाफा।

एमजी मोटर: हेक्टर, एस्टर और इलेक्ट्रिक कारों के दाम 2% तक बढ़े।

रेनॉ इंडिया: क्विड, ट्राइबर और काइगर जैसी कारें अब 2% तक महंगी।

हुंडई इंडिया: क्रेटा, वेन्यू और i20 समेत पूरी रेंज पर कीमतों में 0.6% की बढ़ोतरी।

बीवायडी इंडिया: एटो 3 और सील के दाम बढ़ाने का ऐलान। कितने बढ़ेंगे यह साफ नहीं।

होंडा कार्स: सिटी और अमेज की कीमतों में भी बदलाव होगा। दाम कितने बढ़ेंगे यह साफ नहीं।

सीएनजी और घरेलू पीएनजी सस्ती होंगी : पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) ने 1 जनवरी 2026 से गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को कम किया है। इसके बाद देश के अलग-अलग राज्यों में सीएनजी और घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी की कीमतें 2-3 प्रति यूनिट तक घट जाएंगी।

एविएशन फ्यूल के दाम घटने से हवाई टिकट सस्ता हो सकता है :नए साल पर हवाई यात्रा करने वालों को राहत मिलने की उम्मीद है। तेल कंपनियों ने एविएशन फ्यूल के दाम करीब 7 हजार रुपए घटा दिए हैं। दिल्ली में फ्यूल के दाम 99,676.77 से घटकर 92,323.02 प्रति किलोलीटर हो गए हैं। कीमतों में आई इस कमी से एविएशन कंपनियों की ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगी, जिसका सीधा फायदा हवाई टिकटों के दाम कम होने के रूप में यात्रियों को मिल सकता है।

आठवें वेतन आयोग से बढ़ सकती है सैलरी : केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने का ऐलान किया है। अभी टाइमलाइन नहीं बताई गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यह जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।

संपादकीय

सामाजिक सुरक्षा का सवाल

यह ठीक है कि खाने-पीने की सामग्री के साथ अन्य सामान की डिलीवरी करने वाले अस्थायी कामगारों यानी गिग वर्करों की ओर देश का ध्यान गया, लेकिन ऐसा तब हो पाया, जब विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाले इन लोगों को हड़ताल करनी पड़ी। गिग वर्करों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिए, क्योंकि उनकी कार्यदशाएं काफी कठोर हैं।आज जब क्विक कामर्स और फूड डिलीवरी कंपनियों का कारोबार बढ़ता जा रहा है, तब उनके लिए काम की बेहतर दशाएं सुनिश्चित की ही जानी चाहिए। यह संतोषजनक तो है कि केंद्र सरकार गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक प्रस्ताव लेकर आई है, लेकिन बात तब बनेगी, जब इस प्रस्ताव के प्रविधानों को सही तरह लागू करने में सफलता मिलेगी। गिग वर्करों की समस्या यह है कि वे जिन कंपनियों के लिए काम करते हैं, उनके वे कर्मचारी नहीं माने जाते। उनके काम के घंटे भी तय नहीं हैं। वे जितने समय काम करते हैं, उतने ही वक्त का उन्हें पैसा मिलता है। उन्हें कभी भी काम से हटाया जा सकता है। चूंकि उनकी स्थिति असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसी है, इसलिए उनकी कार्यदशाओं पर किसी का ध्यान नहीं है। यदि उनके साथ कुछ अनहोनी जाए तो संबंधित कंपनी की जवाबदेही नहीं होती। यह समझा जाना चाहिए कि गिग वर्कर आधारित उद्योग बेहतर नियमन की मांग कर रहा है। गिग वर्करों की समस्याएं इसलिए और बढ़ गई हैं, क्योंकि दस मिनट में भी सामान की डिलीवरी करने का चलन जोर पकड़ गया है। इस चलन पर फिर से विचार होना चाहिए, क्योंकि इससे गिग वर्करों के साथ दुर्घटनाएं होने का जोखिम बढ़ गया है। कई बार गिग वर्कर शीघ्र सामान पहुंचाने के फेर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते दिखते हैं। निस्संदेह गिग वर्कर बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें मिलने वाले मेहनताने को आकर्षक नहीं कहा जा सकता। नीति आयोग के अनुसार 2020-21 में जो गिग वर्कर 77 लाख के करीब थे, उनकी संख्या 2029-30 तक 2.35 करोड़ हो जाएगी। ऐसे में सरकार के साथ उन कंपनियों को भी उनकी सुधि लेनी होगी, जिनके लिए वे काम करते हैं। उन्हें केवल सामाजिक सुरक्षा के ही दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए, बल्कि ऐसे उपाय भी किए जाने चाहिए, जिससे उनका शोषण न हो सके और वे अपने भरणपोषण लायक आय अर्जित कर सकें। अब जब यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में गिग वर्करों की संख्या बढ़ती ही जानी है, तब इस पर भी ध्यान दिया जाए कि सामान की डिलीवरी के लिए बैट्री चालित दोपहिया वाहनों का ही उपयोग हो। यह भी समय की मांग है कि गिग वर्करों के साथ असंगठित क्षेत्र के अन्य सभी कामगारों के हित की भी चिंता की जाए।

दिग्विजय सिंह की वैचारिक उलझनें

अपनी मजबूरियों और विरोधाभासों के बीच कांग्रेस ने इस समस्या को सलीके से दफना दिया। अकादमिक जगत के लोग और विशेषज्ञ इसे नर्म हिंदुत्व कहते हैं। पार्टी में अनुष्ठान वाले हिंदुत्व के पैरोकार भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कमलापति त्रिपाठी बहुत मुखरता से हिंदुत्व के प्रतीक चिह्न धारण करते थे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून पारित किया गया। इसका नाम था मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968। इससे पहले यानी 1954 में ही कांग्रेस की राज्य सरकार ने नियोगी समिति का गठन किया था ताकि धर्मांतरण और मिशनरी गतिविधियों की जांच की जा सके।

आदिति फडणीस : लेखक बैजनाथ से हैं

वह कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। इसके बावजूद वह समय-समय पर खुद को और अपनी पार्टी को वैचारिक विवादों में उलझा देते हैं। इससे यही संकेत निकलता है कि कांग्रेस की अपनी वैचारिक खोज की यात्रा निरंतर जारी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य सभा सदस्य (उनका कार्यकाल इस वर्ष के अंत में समाप्त हो रहा है) दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के केंद्रीय नियंत्रण और पुरस्कृत करने के ढांचे की जो तारीफ की है उसने कांग्रेस में एक बार फिर हलचल पैदा की है।

उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें युवा नरेंद्र मोदी भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के चरणों में बैठे हुए हैं। सिंह ने लिखा कि यह तस्वीर बहुत प्रभावशाली है और भाजपा-आरएसएस जमीनी कार्यकर्ताओं को संगठन के भीतर मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री जैसे वरिष्ठ पद तक पहुंचने का अवसर देते हैं। उनकी एक अन्य पोस्ट जिसे भाजपा समर्थकों ने उद्धृत किया उसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने सीधे पार्टी नेता राहुल गांधी को संबोधित करते हुए लिखा, 'जिस तरह ईसीआईएसवीईईपी (चुनाव आयोग के एक कार्यक्रम) को सुधारों की जरूरत है उसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी... हमें अधिक व्यावहारिक और विकेंद्रीकृत प्रणाली की जरूरत है।'

पार्टी के कुछ सदस्यों का कहना है कि वास्तव में दिग्विजय सिंह का सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस, भाजपा जैसी क्यों नहीं बन सकती? वर्ष2018 के मध्य प्रदेश विधान सभा चुनावों के पहले उन्होंने पैदल नर्मदा परिक्रमा शुरू की थी। 2023 के विधान सभा चुनाव के पहले उन्होंने भगवा धारण कर दतिया की पीतांबर पीठ में पूजा अर्चना की। इसके पहले वह 35 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा में शामिल हुए जो जबलपुर के ग्वारीघाट से शुरू हुई और कैलाश धाम तक चली। यात्रा में एक लाख से अधिक लोग शामिल हुए और दिग्विजय सिंह को नंगे पैर चलते देखा गया। उन्होंने कुछ देर कांवड़ भी उठाई।

ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने 2010 में कांग्रेस के बुराड़ी अधिवेशन में भाजपा और आरएसएस जैसी 'फासीवादी ताकतों' पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था, 'आरएसएस अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा की ओट में मुसलमानों को उसी तरह निशाना बना रहा है जिस तरह 1930 के दशक में नाज़ियों ने यहूदियों को बनाया था।' उन्होंने कहा था कि आरएसएस नई पीढ़ी के मन में मुस्लिम विरोध वाली नफरत के बीज बो रहा है और यह सबसे बड़ा खतरा है।

उन्होंने आरोप लगाया था कि आरएसएस अपने कार्यकर्ताओं को अफसरशाही और सेना में भी प्रवेश दिला रहा है। उन्होंने यह प्रश्न भी किया था कि 'आखिर क्यों मालेगांव, मक्का मस्जिद, समझौता एक्सप्रेस जैसे तमाम धमाकों में शामिल सभी लोगों का संबंध आरएसएस से ही था?' इस प्रकार उन्होंने हिंदू आतंकवाद पर प्रभावी ढंग से बहस आरंभ कर दी थी।

अपनी मजबूरियों और विरोधाभासों के बीच कांग्रेस ने इस समस्या को सलीके से दफना दिया। अकादमिक जगत के लोग और विशेषज्ञ इसे नर्म हिंदुत्व कहते हैं। पार्टी में अनुष्ठान वाले हिंदुत्व के पैरोकार भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कमलापति त्रिपाठी बहुत मुखरता से हिंदुत्व के प्रतीक चिह्न धारण करते थे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून पारित किया गया। इसका नाम था मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968। इससे पहले यानी 1954 में ही कांग्रेस की राज्य सरकार ने नियोगी समिति का गठन किया था ताकि धर्मांतरण और मिशनरी गतिविधियों की जांच की जा सके। ये उदाहरण बताते हैं कि कांग्रेस में हिंदुत्व की विचारधारा मौजूद थी।

यह कांग्रेस की उस वैचारिकी की पृष्ठभूमि है जिससे दिग्विजय सिंह निकले हैं। परंतु वह एक छिपे हुए हिंदुत्ववादी या कट्टर आरएसएस विरोधी नेता भर नहीं है। 1993 से 2003 तक यानी काफी साल पहले वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अर्जुन सिंह के शिष्य के रूप में शुरुआत करने वाले सिंह ने उस समय कई प्रशासनिक सुधार किए जो उन पर ही भारी पड़ गए। उन्होंने 73वें संविधान संशोधन का लाभ उठाते हुए विकेंद्रीकरण और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत किया, जिससे जिला पंचायतों के सरपंचों को स्वायत्तता और शक्ति मिली। लेकिन इससे विधायक स्वयं को शक्तिहीन महसूस करने लगे और उनकी ही पार्टी के विधायक उन पर सवाल उठाने लगे। मध्य प्रदेश की सड़क अधोसंरचना अच्छी नहीं थी। यद्यपि सिंह ने सड़कों के लिए बजटीय प्रावधान किए, लेकिन इसका केवल एक छोटा हिस्सा वास्तविक रखरखाव पर खर्च हुआ, जबकि अधिकांश हिस्सा राज्य-स्वामित्व वाली सड़क विकास निगम के कर्मचारियों के वेतन पर चला गया। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश के विभाजन और छत्तीसगढ़ के गठन के बाद, 32 फीसदी बिजली उत्पादन क्षमता छत्तीसगढ़ में चली गई। मध्य प्रदेश के पास दो विकल्प थेः जल्दी से विद्युत उत्पादन बढ़ाना और छत्तीसगढ़ से बिजली खरीदना। लेकिन इस बीच, राज्य कुछ समय के लिए 50 फीसदी बिजली की कमी से जूझता रहा। किसानों और अन्य उपभोक्ता वर्गों को मुफ्त बिजली देने का वादा करने के बाद, सिंह को नाराज उपभोक्ताओं के गुस्से का सामना करना पड़ा।

बाजार नियामक की ताकत कमजोर होने का खतरा

आरबीआई के अधिशेष फंड को समेकित निधि में हस्तांतरित करने से इसकी तुलना करना पूरी तरह से गलत है। सरकार केंद्रीय बैंक को मुद्रा छापने और जारी करके आय अर्जित करने की अनुमति देती है। आरबीआई विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधियों और कार्यों से भी आय अर्जित करता है। आरबीआई द्वारा सरकार को फंड का हस्तांतरण लाभांश भुगतान की श्रेणी में आता है। तर्क को छोड़ दें तो, इसमें शामिल राशियों की तुलना कैसे की जा सकती है? जहां आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 के लिए सरकार को लगभग 2.69 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए, वहीं सेबी के सामान्य कोष की वित्त वर्ष 2024 के लिए समापन शेष और अधिशेष राशि क्रमशः केवल 5,500 करोड़ रुपये और 1,000 करोड़ रुपये थी। अधिशेष निधि का हस्तांतरण सरकार की बजट राजस्व आवश्यकताओं के लिए ऊंट के मुंह में जीरा जैसा होगा।

अजय त्यागी : 'स्वतंत्र लेखक'

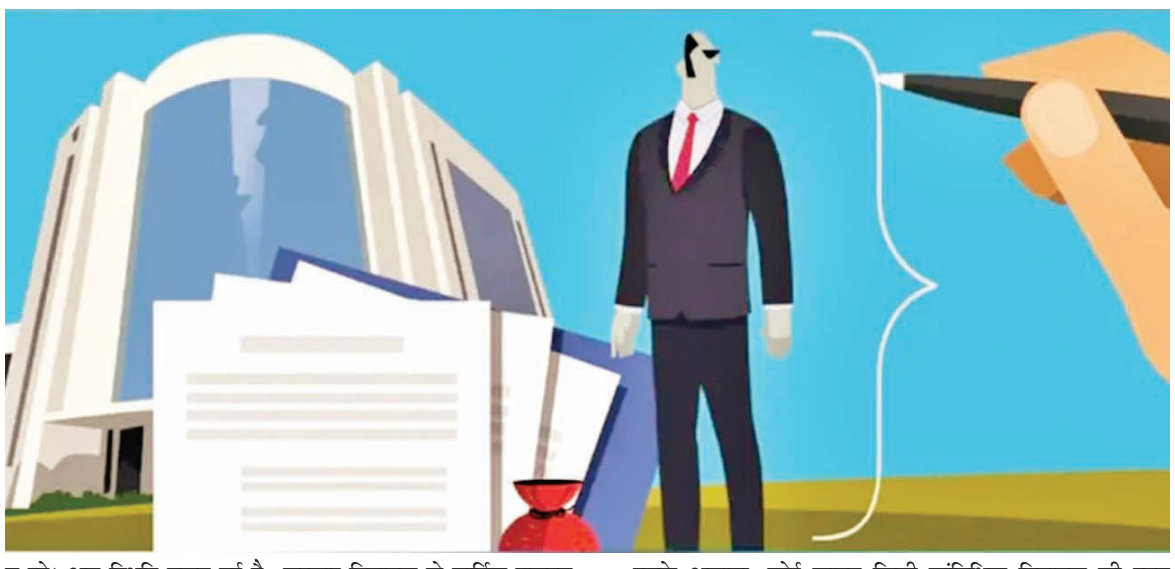

संसद के हाल ही में समाप्त हुए शीतकालीन सत्र में सरकार ने प्रतिभूति बाजारों से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए प्रतिभूति बाजार संहिता, 2025, विधेयक पेश किया। यह लेख विधेयक के खंड 124 पर केंद्रित है, जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के वार्षिक अधिशेष सामान्य कोष को भारत की संचित निधि (सीएफआई) में हस्तांतरित करने से संबंधित है।

अब सवाल यह है कि मौजूदा प्रावधानों में प्रस्तावित परिवर्तन क्या है? इस कोष में कितना पैसा आता है और कितना जाता है? संक्षेप में कहें तो सेबी द्वारा बाजार से जुड़े अवसंरचना संस्थानों, विनियमित संस्थाओं और बाजार प्रतिभागियों पर लगाए गए शुल्क और प्रभार इस फंड में आने वाले धन का हिस्सा हैं। इस फंड का उपयोग नियामक के राजस्व और पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। नियामक का वार्षिक बजट उसके बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है। एक वित्तीय रूप से स्वायत्त संस्था से इसी प्रकार कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

अब, प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, कानून नियामक की वार्षिक निधि आवश्यकता की अधिकतम सीमा निर्धारित करता है, और अधिशेष रकम समेकित निधि को प्राप्त होगी। खंड124 के प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैं:

'... (3) बोर्ड एक आरक्षित निधि तैयार करेगा और किसी भी वित्त वर्ष में सामान्य कोष के वार्षिक अधिशेष का 25 फीसदी ऐसी आरक्षित निधि में जमा किया जाएगा। यह पिछले दो वित्त वर्षों के वार्षिक व्यय के योग से अधिक नहीं होगा।

(5) उप धारा (3) के अधीन वार्षिक अधिशेष के अंश को जमा करने के बाद, उस वित्त वर्ष के लिए सामान्य निधि का शेष वार्षिक अधिशेष भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा...'

इस खंड से संबंधित विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार है: 'विधेयक के खंड124 में यह प्रावधान है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित सामान्य कोष को संहिता के प्रयोजनों के लिए निधि माना जाएगा।' इसमें न तो नियामक द्वारा आरक्षित निधि के गठन और अधिशेष राशि को समेकित निधि को हस्तांतरित करने के उद्देश्य का वर्णन है और न ही इसके बारे में कोई चर्चा!

तो मौजूदा प्रावधानों में इस बदलाव के प्रस्ताव का तर्क क्या है? सार्वजनिक रूप से उपलब्ध टिप्पणियों से पता चलता है कि सरकार ने वर्षों से सेबी के कोष में अत्यधिक वृद्धि देखी और बजट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस अधिशेष को अपने पास हस्तांतरित करने के अपने अधिकार पर विचार किया, जिसके चलते यह बदलाव किया गया। कुछ लोग इसकी तुलना कुछ वर्ष पहले सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अधिशेष कोष को समेकित निधि में हस्तांतरित करने से करते हैं। यह तर्क कई मायनों में निराधार है।

सेबी अधिनियम, 1992 के तहत सेबी के सामान्य कोष की स्थापना का तर्क काफी सीधा था- यानी नियामक को अपने खर्च पूरे करने के लिए आय अर्जित करने में सक्षम बनाना ताकि वह सरकारी अनुदानों पर निर्भर न रहे। अब स्थिति उलट गई है- सरकार नियामक से वार्षिक राजस्व प्राप्त करने की कोशिश कर रही है!

विनियमित संस्थाओं पर लगाए गए शुल्क और प्रभार ही सेबी की आय का एकमात्र स्रोत हैं, इसलिए किसी भी समय इनकी मात्रा निर्धारित करते समय नियामक का अल्प से मध्यम अवधि का अनुमानित व्यय प्रमुख कारक हो सकता है। नियामक से अपेक्षा की जाती है कि वह नियमित रूप से शुल्क और प्रभारों को समायोजित करे ताकि निधि में आने वाली राशि अनुमानित व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। यह स्वीकार किया जाता है कि कई बार अनुमान लगाने में सावधानी बरतने के बावजूद प्राप्तियों और व्यय राशि में अंतर हो सकता है। हाल के वर्षों में सेबी की निधि में अधिशेष के बड़े पैमाने पर जमा होने का एक कारण भारत के पूंजी बाजारों में बढ़ती गतिविधि है, जिसमें प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि और नई संस्थाओं का प्रवेश शामिल है। इस स्थिति को सुधारने के लिए नियामक के लिए पहला कदम यह होना चाहिए था कि उचित विश्लेषण के बाद शुल्क और प्रभारों को उचित रूप से कम किया जाए और इसका लाभ विनियमित संस्थाओं को दिया जाए।

किसी भी स्थिति में बाजार नियामक द्वारा विनियमित संस्थाओं और बाजार प्रतिभागियों पर लगाए गए शुल्क और प्रभार वैध रूप से सरकार के लिए वार्षिक राजस्व का स्रोत नहीं बन सकते। ये कर या शुल्क नहीं हैं। न ही इस हस्तांतरण को सेबी द्वारा सरकार को दिया गया लाभांश माना जा सकता है। इस परिभाषा में एक बड़ी समस्या यह है कि एक बार सेबी से होने वाली आय सरकार के घाटे वाले बजट के लिए वार्षिक राजस्व का स्रोत बन जाए, तो इस तरह की प्राप्तियों को साल-दर-साल बढ़ाने का लगातार दबाव बना रहेगा। यह बेतुका है क्योंकि इसका अर्थ होगा- नियामक को विनियमित संस्थाओं से अधिक से अधिक आय अर्जित करने का दायित्व सौंपना ताकि सरकार का बजट चलाया जा सके। यह भी स्पष्ट नहीं है कि प्रस्तावित वार्षिक हस्तांतरण कानूनी रूप से मान्य है या नहीं।

इसके अलावा, कोई कानून किसी सांविधिक नियामक की व्यय आवश्यकताओं पर मनमाने ढंग से सीमा कैसे तय कर सकता है? फिर नियामक के सरकार से स्वतंत्र रूप से काम करने के बुनियादी और सर्वमान्य अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत का पालन करने का भी प्रश्न उठता है। ध्यान दें कि बाजार नियामक सरकारी स्वामित्व वाली सूचीबद्ध कंपनियों को भी नियंत्रित करता है। हितों के किसी भी संभावित टकराव, या यहां तक कि इसकी आशंका से भी बचना जरूरी है। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपने वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम रिपोर्ट में इस पर कड़ी टिप्पणी किए जाने के आसार हैं।

आरबीआई के अधिशेष फंड को समेकित निधि में हस्तांतरित करने से इसकी तुलना करना पूरी तरह से गलत है। सरकार केंद्रीय बैंक को मुद्रा छापने और जारी करके आय अर्जित करने की अनुमति देती है। आरबीआई विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधियों और कार्यों से भी आय अर्जित करता है। आरबीआई द्वारा सरकार को फंड का हस्तांतरण लाभांश भुगतान की श्रेणी में आता है। तर्क को छोड़ दें तो, इसमें शामिल राशियों की तुलना कैसे की जा सकती है? जहां आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 के लिए सरकार को लगभग 2.69 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए, वहीं सेबी के सामान्य कोष की वित्त वर्ष 2024 के लिए समापन शेष और अधिशेष राशि क्रमशः केवल 5,500 करोड़ रुपये और 1,000 करोड़ रुपये थी। अधिशेष निधि का हस्तांतरण सरकार की बजट राजस्व आवश्यकताओं के लिए ऊंट के मुंह में जीरा जैसा होगा।

तो बाजार नियामक के पास जमा अतिरिक्त कोष से निपटने का उपाय क्या है? जैसा कि पहले बताया गया है, पहला कदम शुल्क और प्रभार कम करना होना चाहिए। यदि किसी भी समय अतिरिक्त निधि बहुत अधिक हो जाती है, और निकट भविष्य में इसके निष्क्रिय और अप्रयुक्त रहने की संभावना है, तो बोर्ड सरकार को एकमुश्त राशि हस्तांतरित करने का निर्णय ले सकता है। बेशक, इसे एक बार की कार्रवाई मानी जानी चाहिए, और इसे नियम या मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए।

आज का राशिफल

मेष राशि आज साल का पहला दिन मेष राशि के लिए उम्मीद और आनंद से लबरेज रहेगा। आपका दिन आज सुखद बीतेगा। आप मनोरंजक समय का आनंद ले पाएंगे। यात्रा का भी आज संयोग बन सकता है। आपको परिवार और दोस्तो का भी साथ मिलेगा।

वृषभ राशि के जातको के लिए आज का दिन घर परिवार के मामले में सुखद रहेगा। आपको आज परिवार के साथ कहीं यात्रा का मौका मिलेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी ज सकते हैं। पिता से आपको सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा।

मिथुन राशि आज साल के पहले दिन मिथुन राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। आपकी कोई चाहत पूरी होगी। किसी सगे संबंधी से मिलने का संयोग बनेगा। आप मनोरंजक समय का आनंद लेगे। दिन के पहले भाग मे आज आपको कुछ जरूरी काम भी निपटाने होंगे।

कर्क राशि आज का दिन कर्क राशि के लिए मिलाजुला रहेगा। दिन के पहले भाग मे आज कुछ उलझन का सामना करना होगा। लेकिन दिन का दूसरा भाग आपका मनोरंजक बितेगा। आपको आज कोई खुशखबरी मिल सकती है। बिजनेस में कमाई होने का योग बना है।

सिंह राशि आज का दिन सिंह राशि लिए जोश और उत्साह से भरपूर रहेगा। आपको आज दोस्तों के साथ सुखद और मनोरंजक समय बिताने का मौका मिलेगा। आप कोई नया काम भी आज शुरू कर पाएंगे। आपके घर आज किसी सगे संबंधी का भी आगमन हो सकता है।

कन्या राशि आज 1 जनवरी का दिन कन्या राशि के लिए आनंददायक रहने वाला है। आपको आज सगे संबंधियों से सहयोग मिलेगा। मित्रो के साथ आज आप मनोरंजक समय बिता पाएंगे। आपको आज रुचिकर भोजन मिलने की खुशी होगी।

तुला राशि आज का दिन तुला राशि के जातको के रोमांटिक रहेगा। आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का तनाव चल रहा है तो वह दूर होगा। आपके रिश्ते में प्रेम और तालमेल बना रहेगा। आपको आज कोई खुशखबरी मिल सकती है। आप प्रेमी के साथ आज कहीं घूमने का भी प्लान बना सकते हैं।

वृश्चिक राशि आज का दिन वृश्चिक राशि के जातको के लिए उत्साह से भरपूर रहेगा। आप आज सुबह से ही एक्टिव मोड में रहेगे। दोस्तों के साथ आज मनोरंजक समय बीतेगा लेकिन आपको आज किसी बात को लेकर विवाद और जिद करने से बचना चाहिए।

धनु राशि आज का दिन धनु राशि के लोगों के लिए मंगलकारी रहेगा। आप आज धर्म कर्म के काम में रुचि लेंगे। घर के वरिष्ठ सदस्यों से आपको आज पूरा सहयोग मिलेगा। पिता और पिता पक्ष से आपको आज सहयोग मिलेगा। कोई सोचा हुआ काम पूरा होने से आपका मन आज आनंदित होगा।

मकर राशि के जातको के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा। आपको आज अतिउत्साह में जोखिम लेने से बचना चाहिए। यात्रा पर जा रहे हैं तो वाहन सावधानी से चलाएं और मांस मदिरा के सेवन से परहेज करें। किसी सगे संबंधी की वजह से मूड खराब हो सकता है।

कुंभ राशि के जातको के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा। आपको आज अपने खर्च पर कंट्रोल करना होगा। आपके लिए आज सितारे बताते हैं कि अपने खान पान पर संयम रखें और जोखिम लेने से बचें। आपको आज परिवार से सहयोग मिलेगा।

मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। आप आज किसी धार्मिक और शुभ काम में भाग ले पाएंगे। आज आपको पिता और वरिष्ठजनों से सहयोग मिलेगा। आप आज वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी को कहीं घुमाने ले जा सकते हैं। आपको आज आर्थिक लाभ मिलेगा लेकिन खर्च भी बना रहेगा।

मजदूर भी फंसे, अचानक खुला डैम का गेट

ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में बना अप्रोच रोड बहा

खंडवा » हिन्द शिला

ओंकारेश्वर बांध प्रबंधन की एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिना पूर्व सूचना अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने से रेलवे ब्रिज निर्माण के लिए बनाया गया एप्रोच रोड बह गया। नर्मदा नदी के बीच काम कर रहे मजदूरों की जान जोखिम में पड़ गई। गनीमत रही कि समय रहते नावों की मदद से सभी मजदूरों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया।

नर्मदा में बहा एप्रोच रोड, 10 मजदूर नदी के बीच फंसे

मोरटक्का क्षेत्र में नर्मदा नदी पर रेलवे ब्रिज निर्माण का कार्य मंगलम बिल्डकॉन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। निर्माण कार्य के लिए नदी में अस्थायी एप्रोच रोड बनाया गया था, जिससे मजदूर और निर्माण सामग्री की आवाजाही हो रही थी। बताया जा रहा है कि ओंकारेश्वर डैम से बिजली उत्पादन के लिए अचानक टरबाइन के माध्यम से अधिक पानी छोड़ दिया गया, जिससे तेज बहाव में एप्रोच रोड बह गया। इसी दौरान काम कर रहे कंपनी के 10 मजदूर नर्मदा नदी के बीच फंस गए।

नावों की मदद से किया गया रेस्क्यू, टली बड़ी दुर्घटना

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों और प्रशासन को सूचित किया गया। इसके बाद नावों की मदद से सभी मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू के दौरान मजदूरों में भय का माहौल बना रहा। यदि समय रहते मदद नहीं मिलती तो बड़ा हादसा हो सकता था।

एप्रोच रोड बनने तक ठप्प रहेगा रेलवे ब्रिज निर्माण कार्य

मंगलम बिल्डकॉन कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि एप्रोच रोड के बह जाने से रेलवे ब्रिज का निर्माण कार्य पूरी तरह ठप्प हो गया है। कंपनी प्रबंधन के अनुसार, नई एप्रोच रोड बनाने में कम से कम 10 दिन का समय लगेगा, उसके बाद ही मजदूरों को दोबारा काम पर लगाया जा सकेगा। इससे परियोजना की समय-सीमा पर भी असर पड़ने की संभावना है। इस रेलवे ब्रिज के निर्माण को क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्रिज के पूरा होने के बाद खंडवा से इंदौर की यात्रा मात्र 1 घंटे में पूरी की जा सकेगी, जिससे व्यापार, आवागमन और विकास को बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन बार-बार हो रही लापरवाही और सुरक्षा उपायों की अनदेखी से न सिर्फ परियोजना में देरी हो रही है, बल्कि मजदूरों की जान भी खतरे में पड़ रही है।

खेड़ीघाट पर दुकानदारों की दुकानें डूबीं

डैम से टरबाइन का अचानक पानी छोड़े जाने का असर केवल निर्माण स्थल तक ही सीमित नहीं रहा। खेड़ीघाट क्षेत्र में नर्मदा किनारे दुकान लगाकर रोजी-रोटी चलाने वाले दुकानदारों की दुकानें भी पानी में डूब गईं। दुकानदारों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इसी तरह बिना सूचना पानी छोड़े जाने से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। दुकानदारों ने डैम प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की है।

डैम प्रबंधन पर उठे सवाल, जांच की मांग

इस घटना के बाद ओंकारेश्वर डैम प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों, मजदूरों और दुकानदारों ने मांग की है कि बिना सूचना पानी छोड़ने की जिम्मेदारी तय की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और डैम प्रबंधन की जवाबदेही तय होती है या नहीं।

जबलपुर में जहरीली शराब से 19 मौतें

घर के घर खत्म हो रहे और प्रशासन को भनक नहीं, तस्वीरें लेकर पहुंचे लोग

जबलपुर » हिन्द शिला

इंदौर में पानी त्रासदी के बाद जबलपुर में जहरीली शराब ने कहर बरपाया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीते कुछ महीनों में 19 लोगों की मौत हो गई है। इसे लेकर बड़ी संख्या में कॉलोनी के लोगों ने प्रदर्शन किया है। साथ ही मृतकों की तस्वीर लगे बैनर लेकर भी पहुंचे थे। स्थानीय लोगों का आरोप था कि सब कुछ पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है। अवैध शराब की बिक्री के बारे में पुलिस को खबर है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है।

यह घटना जबलपुर के बाबा टोला और सिंधी कैंप के इलाकों की है। लोगों का कहना है कि जहरीली शराब से लगातार मौतें हो रही हैं लेकिन प्रशासन खामोश है। हाथ में तख्तियां लेकर आए लोगों को देखकर पता चल रहा था कि यह सिर्फ मौत के आंकड़े नहीं, बल्कि टूटे हुए परिवारों, खामोश घरों और अधूरी रह गई जिंदगियों की दास्तान है। लोगों के साथ-साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने एसपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया है। साथ ही त्रासदी के बारे में बताया है।

शराब की लत ने परिवार खत्म कर दिया

प्रदर्शन करने आई महिला माया बाई ने बताया कि उनकी आंखों के आंसू अभी सूखे नहीं है। पति के साथ माया बाई के दो बेटे थे लेकिन शराब की लत ने सबको छीन लिया। शराब ने एक-एक कर उनकी जानें ले ली। अब माया बाई अकेली हैं। सहारा सिर्फ बेटी और बहू हैं। परिवार को समझाने की कोशिश की लेकिन सस्ती शराब की लालच में उनलोगों ने एक नहीं सुनी। वह कहती हैं कि शराब बंद नहीं हुई तो मोहल्ले के नौजवान खत्म हो जाएंगे।

मध्य प्रदेश गृह विभाग ने भर्ती नियमों में किया संशोधन किया

एमपी पुलिस में 'सिंघम' बनेंगे थर्ड जेंडर

भोपाल » हिन्द शिला

मध्य प्रदेश पुलिस में अब किन्नर भी भर्ती हो सकेंगे। गृह विभाग ने पुलिस भर्ती नियमों में संशोधन कर राजपत्र में सूचना जारी की है। इसके अनुसार थर्ड जेंडर को भी पुलिस भर्ती में मौका दिया जाएगा। इनको ओबीसी कैटेगिरी में माना जाएगा।

मध्य प्रदेश के पुलिस बेड़े में अब एक नया और गौरवशाली अध्याय जुड़ने जा रहा है। अब तक जिन हाथों को समाज ने सिर्फ दुआएं देने या नेक मांगने के लिए देखा था, अब उन्हीं हाथों में कानून की रक्षा का डंडा और कमर पर पिस्टल सजी होगी। मध्य प्रदेश सरकार के नए नोटिफिकेशन ने थर्ड जेंडर समुदाय के लिए पुलिस में कमांडेंट और सब-इंस्पेक्टर बनने का रास्ता साफ कर दिया है। यह बदलाव सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति है। अब थर्ड जेंडर के युवा न केवल आरक्षक बनेंगे, बल्कि अपनी योग्यता के दम पर ऊंचे पदों पर बैठकर अपराधियों के छक्के छुड़ाएंगे।

भर्ती की खास बात यह है कि कलेक्टर कार्यालय से मिलने वाला एक 'मैजिकल सर्टिफिकेट' यह तय करेगा कि उनकी शारीरिक परीक्षा पुरुष वर्ग के कठिन मानकों पर होगी या महिला वर्ग के कोमल लेकिन चुनौतीपूर्ण मानदंडों पर।

क्यों खास है यह फैसला?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जमीन पर उतारते हुए एमपी पुलिस ने भेदभाव की दीवार ढहा दी है। भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग सेंटर के उबड़-खाबड़ रास्तों और कड़क अनुशासन में भी इन्हें महिला या पुरुष वर्ग के समान ही तैयार किया जाएगा। जब एक ट्रांसजेंडर अफसर परेड की कमान संभालेगा, तो समाज में उनके प्रति नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा।

विदेश में किए गए अपराध की जांच कर सकती है पुलिस, अहम फैसला

जबलपुर » हिन्द शिला

मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई अपराध विदेश में घटित होता है, तो उसके विरुद्ध भारत में दर्ज की गई एफआईआर को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता कि केंद्र सरकार से अभी तक मंजूरी नहीं ली गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 188 (CrPC) के तहत मंजूरी की आवश्यकता ट्रायल के स्तर पर होती है, न कि पुलिस जांच के प्रारंभिक चरण में के लिए। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने व्यवस्था दी कि पुलिस एफआईआर दर्ज कर प्रारंभिक जांच कर सकती है। धारा 188 के तहत केंद्र की अनुमति तब अनिवार्य होती है जब अदालत मामले पर संज्ञान लेती है या ट्रायल शुरू होता है। कोर्ट ने पाया कि पीड़िता के आरोपों के अनुसार, प्रताड़ना केवल जापान में नहीं, बल्कि भारत लौटने के बाद भी जारी रही, जिससे भारतीय पुलिस का क्षेत्राधिकार वैध बनता है। बता दें कि हाईकोर्ट में यह याचिका जापान निवासी वैभव जैन और उनके माता-पिता जो कि जयपुर राजस्थान निवासी हैं, उनके द्वारा दायर की गई थी। उनके खिलाफ भोपाल के महिला थाने में दहेज प्रताड़ना और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज है। वैभव और उनकी पत्नी जापान में नौकरी करते थे और उनका विवाह जनवरी 2023 में जयपुर में हुआ था। पत्नी का आरोप था कि जापान में ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित किया, जिसके बाद वह भोपाल लौट आईं। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि चूंकि घटना जापान की है, इसलिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना जांच शुरू नहीं की जा सकती। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वर्तमान में पुलिस केवल जांच कर रही है और अभी तक चार्जशीट दायर नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में, एफआईआर को रद्द करने का कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि 'रिकॉर्ड के अनुसार, प्रताड़ना भारत में भी जारी रही।

सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत बोले-

हमारा धर्म, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था महिलाओं के कारण ही सुरक्षित है

भोपाल » हिन्द शिला

भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा शिवनेरी भवन में आयोजित मातृशक्ति संवाद कार्यक्रम में सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने महिलाओं की भूमिका को समाज, संस्कृति और राष्ट्र की धुरी बताया। उन्होंने कहा कि हमारा धर्म, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था महिलाओं के कारण ही सुरक्षित है। कार्यक्रम की मूल भावना "नारी तू ही नारायणी" रही, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण, प्रबोधन और सामाजिक जिम्मेदारी पर गंभीर विमर्श हुआ। मंच पर प्रांत संघचालक अशोक पांडेय और विभाग संघचालक सोमकांत उमालकर उपस्थित रहे।

डॉ. भागवत ने कहा कि अब वह समय नहीं रहा जब महिलाओं को केवल सुरक्षा के नाम पर घर तक सीमित रखा जाए। आज परिवार और समाज दोनों को स्त्री-पुरुष मिलकर आगे बढ़ाते हैं, इसलिए दोनों का वैचारिक प्रबोधन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अवसर देना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और उनके विचारों को मजबूती देना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इसे और अधिक सशक्त बनाने की जरूरत है।

सामाजिक चुनौतियों पर बोलते हुए सरसंघचालक ने कहा कि लव जिहाद जैसी समस्याओं की रोकथाम का पहला दायित्व परिवार का है। उन्होंने इसका बड़ा कारण परिवारों में संवाद की कमी बताया। उन्होंने कहा कि जब परिवार में खुला और निरंतर संवाद होगा, तब बेटियां बहकावे का शिकार नहीं होंगी। उन्होंने तीन स्तरों पर प्रयास की बात कही- परिवार के भीतर संवाद, बच्चियों को आत्मरक्षा और सावधानी के संस्कार देना, और अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई।डॉ. भागवत ने नारी की भूमिका को सीमित नहीं बल्कि सशक्त बताते हुए कहा कि भारतीय परंपरा में मातृत्व सर्वोच्च स्थान रखता है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में महिला को शक्ति और गरिमा का प्रतीक माना गया है। रानी लक्ष्मीबाई जैसे उदाहरण बताते हैं कि भारतीय नारी हर काल में साहस और नेतृत्व का प्रतीक रही है। कुटुंब व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि परिवार को संतुलित और संवेदनशील बनाए रखने में महिलाओं की भूमिका निर्णायक होती है। पालनकर्ता और सृजनकर्ता के रूप में महिला ही परिवार की धुरी है। उन्होंने कहा कि 'स्व' का भाव घर से समाज और राष्ट्र तक पहुंचाने में भी महिलाओं की अहम भूमिका होती है।

मानसिक स्वास्थ्य पर बोलते हुए डॉ. भागवत ने कहा कि परिवार में कोई भी व्यक्ति अकेला महसूस न करे, यह जरूरी है। अपनापन और संवाद की कमी मानसिक तनाव का बड़ा कारण बनती है। बच्चों पर असंभव अपेक्षाएं न थोपने और उनकी रुचि के अनुसार मार्गदर्शन देने की उन्होंने सलाह दी। अपने संबोधन के अंत में सरसंघचालक ने कहा कि देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और जब मातृशक्ति पूरी तरह जागृत होकर आगे आएगी, तब समाज और राष्ट्र स्वतः सशक्त होंगे। कार्यक्रम का समापन मातृशक्ति को केंद्र में रखकर समाज और राष्ट्र निर्माण के संकल्प तथा वंदे मातरम के साथ हुआ।

आधुनिक और प्राचीन ज्ञान-विज्ञान का अनूठा संगम है गीता भवन : डॉ. यादव

अहिल्याबाई और रानी दुर्गावती की कर्मभूमि पर शुरु हुए गीता भवन

भोपाल » हिन्द शिला

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आम नागरिकों में धार्मिक, आध्यात्मिक और साहित्यिक चेतना के माध्यम से सामाजिक समरसता स्थापित करने प्रदेश में 'गीता भवन' बनाए जा रहे हैं। यह केन्द्र मात्र एक भवन की संरचना नहीं, बल्कि एक जीवंत वैचारिक अध्ययन का केन्द्र है। इनमें आधुनिकता और प्राचीन ज्ञान-विज्ञान के अनूठे संगम में अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रदेश के हर नगरीय निकाय में गीता भवन स्थापित करने का जो संकल्प लिया है, वह तेजी से पूर्ण हो रहा है। यह गर्व का विषय है कि प्रदेश के पहले गीता भवन का शुभारंभ लोकमाता अहिल्याबाई की नगरी इन्दौर में और दूसरा गीता भवन वीरांगना रानी दुर्गावती की कर्मभूमि जबलपुर में शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी राष्ट्र, कोई भी संस्कृति अपनी जड़ों से जुड़कर ही पुष्पित-पल्लवित होती है। गीता भवन संस्कृति को सहेजने और संवर्धित करने का बड़ा माध्यम बनेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गीता भवन राज्य की उस बड़ी पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति, गीता-ज्ञान और पठन-संस्कृति को नई पीढ़ी से जोड़ना है। गीता भवन एक आधुनिक मंच है, जहाँ अध्ययन, चिंतन, शोध और सांस्कृतिक विमर्श के माध्यम से भारतीय दृष्टि को नई पीढ़ी तक पहुँचाया जाएगा। ये भवन अध्ययन, चिंतन और संवाद का जीवंत केंद्र बनेंगे।

गीता भवन में धार्मिक, पौराणिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने वाली, साहित्यिक, प्रेरणादायी जीवनियां, और प्रतियोगी परीक्षाओं आदि की विविध पुस्तकें उपलब्ध हैं। यहाँ वातानुकूलित ई-लाइब्रेरी भी स्थापित की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में हिन्दी, अंग्रेजी एवं संस्कृत में पुस्तकें उपलब्ध हैं। पाठकों की सुविधा के लिए रामायण कक्ष, गीता कक्ष और सर्वधर्म पुस्तक कक्ष भी बनाए गए हैं। गीता भवन में अध्ययन के लिए आने वाले लोगों के लिये सभी सुविधाओं सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रवचनों और शैक्षणिक आयोजनों हेतु खूबसूरत सभागृह भी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में कृष्ण को योगेश्वर श्रीकृष्ण की पहचान देने वाले चारों धामों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन, भगवान श्रीकृष्ण एवं सुदामा का मैत्री स्थल स्वर्णगिरी पर्वत के पास ग्राम नारायणा, धार जिले का अमझेरा और रजोभूमि बदनावर जहां भगवान श्रीकृष्ण ने रात्रि विश्राम किया था।

महाकाल की नगरी में चमत्कार!

स्टेशन पर बंद हुई सासें, फिर ऐसे बची युवक की जान, प्रधान आरक्षक बना देवदूत

उज्जैन » हिन्द शिला

महाकाल ने चमत्कार कर जीवनदान दिया है! उज्जैन में दर्शनों के बाद एक परिवार घर लौट रहा था, इसी दौरान स्टेशन पर युवक को हार्ट अटैक आ गया। उसकी सांसे बंद हो गईं थी। मां-पत्नी और बच्चों में चीख-पुकार मच गई। इतने में पुलिस के एक प्रधान आरक्षक देवदूत बनकर आए, CPR देकर युवक की जान बचा ली। बता दें कि एक हफ्ते में यह दूसरा मौका है, जब सीपीआर देकर खाकी ने जान बचाई थी।

उज्जैन में लोगों की जान बचाने के लिए पुलिसकर्मियों को दी जाने वाली मेडिकल संबंधी सीपीआर की ट्रेनिंग के सुखद परिणाम दिखने लगे है। एक सप्ताह में दूसरी बार खाकी वर्दीधारी ने सीपीआर देकर आम व्यक्ति की जान बचाई है। इस बार एक प्रधान आरक्षक देवदूत बनकर उभरे और 30 साल के युवक की जिंदगी बचा ली। दरअसल उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर साल का पहला दिन था और महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ थी कि पूरा ही प्लेटफार्म खचाखच भरा था।

जानकारी अनुसार प्लेटफार्म नंबर 6 पर शाम करीब पौने पांच बजे, भीड़ के बीच एक परिवार ट्रेन का इंतजार कर रहा था। एकाएक इस परिवार में शामिल 30 साल का नौजवान देवीलाल पिता रामचंद्र निवासी ब्यावरा(राजगढ़) गश खाकर गिर पड़ा। साथ आई पत्नी और मां बिलखने लगे। मां और दादी को रोता देखकर साथ आया बच्चा भी बिलखने लगा था। आसपास लोगों की भीड़ उमड़ गई, हर कोई केवल देख ही रहा था। सलाह दे रहा था पर कोई कुछ कर नहीं सका। इतने में ही प्लेटफार्म पर ड्यूटी दे रहे प्रधान आरक्षक पवन धुर्वे यहां पहुंचे।

तत्काल CPR देना प्रारंभ किया

आरक्षक धुर्वे ने देवीलाल की दिल की धड़कन जांची, कोई हलचल नहीं थी। उन्होंने बिना देर किए देवीलाल को सीपीआर देना शुरु किया और हार्ट को प्रेशर से पंप करना शुरु किया। उनकी मेहनत रंग लाई और चंद मिनट बाद देवीलाल की सांसे लौट आईं। कुछ समय में ही वह पूरी तरह से होश में आ गया। प्रधान आरक्षक ने उसे और उसके पूरे परिवार को ट्रेन में बैठाकर रवाना किया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

प्रधान आरक्षक को मिलेगा सम्मान

घटना को लेकर जीआरपी थाना प्रभारी अमित भावसार ने बताया कि प्रधान आरक्षक ने तत्परता दिखाते हुए सीपीआर देकर यात्री की जान बचाई है। इस सराहनीय कार्य को देखते हुए एसपी द्वारा आरक्षक को सम्मानित और पुरस्कृत किए जाने के लिए विभाग को पत्र लिखा गया है।

मस्जिद के पास अवैध निर्माण हटाने पहुंची थी, आंसू गैस के गोले छोड़े, पुलिसकर्मी-अधिकारी घायल

दिल्ली में आधी रात पुलिस-एमसीडी टीम पर हुई जमकर पत्थरबाजी

नई दिल्ली » हिन्द शिला

दिल्ली में रामलीला मैदान के पास मस्जिद और कब्रिस्तान से सटी जमीन से कल देर रात करीब 1 बजे अतिक्रमण हटाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने 17 बुलडोजर से यहां बने बारात घर, डायग्नोस्टिक सेंटर, दुकानों को ढहाया।

तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास जब इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था, तब भीड़ ने कर्मचारियों और पुलिस पर पथराव किया। भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ कर कार्रवाई रोकने पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर उसे खदेड़ दिया। सेंट्रल रेंज के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मधुर वर्मा ने कहा कि हालात कंट्रोल में हैं। पूरे इलाके को 9 जोन में बांटा गया है। हर जोन की जिम्मेदारी एडीसीपी स्तर के अधिकारी को दी गई। संवेदनशील जगहों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। वीडियो के जरिए पत्थरबाजों की पहचान की जाएगी।

वहीं डीसीपी निधिन वलसन ने कहा कि एमसीडी ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की, जो अभी भी जारी है। भीड़ की पत्थरबाजी में 4-5 अधिकारियों को मामूली चोटें आई हैं।

यह है पूरा मामला

फैज-ए-इलाही मस्जिद की प्रबंधन समिति ने दिल्ली एमसीडी के 22 दिसंबर 2025 के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसमें कहा गया कि मस्जिद के बाहर की 01।95 एकड़ जमीन पर बने ढांचे अवैध हैं। उन्हें हटाया जाएगा। एमसीडी का कहना है कि अतिरिक्त जमीन पर मालिकाना या वैध कब्जे के दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं। एमसीडी का यह आदेश 12 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के निर्देशों के आधार पर जारी किया गया था। डिवीजन बेंच के आदेश में तुर्कमान गेट के पास रामलीला ग्राउंड से करीब 38,940 वर्ग फुट अतिक्रमण हटाने को कहा गया था, जिसमें सड़क, फुटपाथ, बारात घर, पार्किंग और एक निजी क्लिनिक शामिल हैं। मस्जिद समिति का कहना है कि यह जमीन वक्फ संपत्ति है। वह इसके लिए वक्फ बोर्ड को लीज किराया देती है। हमें अतिक्रमण हटाने पर आपत्ति नहीं है। बारात घर और क्लिनिक का संचालन बंद किया जा चुका है। मुख्य आपत्ति कब्रिस्तान को लेकर है।

6 जनवरी : हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मस्जिद और कब्रिस्तान से सटी जमीन से अतिक्रमण (बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर) हटाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने इस मामले में नगर निगम दिल्ली (एमसीडी), शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली वक्फ बोर्ड समेत अन्य विभागों से जवाब मांगा है। जस्टिस अमित बंसल ने कहा था कि मामला सुनवाई के योग्य है। सभी पक्षों को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।

फूड एप से खाना बुलवाना पड़ रहा महंगा

55% यूजर्स ने रेस्टोरेंट से ज्यादा कीमत चुकाई

नई दिल्ली/मुंबई » हिन्द शिला

देशभर में फूड डिलीवरी एप जैसे जोमैटो, स्विगी और ब्लिंकिट को लेकर उपभोक्ताओं और डिलीवरी वर्कर्स की नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोकलसर्किल्स के हालिया सर्वे में 55% उपभोक्ताओं ने कहा कि जब वे इन एप से खाना ऑर्डर करते हैं, तो रेस्टोरेंट में जाकर खाने की तुलना में उन्हें ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं।

इसकी वजह एप द्वारा रेस्टोरेंट से लिया जाने वाला 20 से 30% तक की भारी कमीशन बताया गया है। इसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ता है। इस सर्वे में देश के 359 जिलों के 79 हजार से ज्यादा जवाबों को शामिल किया गया। इनमें 61% पुरुष और 39% महिलाएं थीं।

प्रतिभागियों में 45% टियर 1 शहरों से, 33% टियर 2 शहरों से और 22% टियर 3, 4 और ग्रामीण इलाकों से थे। यह सर्वे लोकलसर्किल्स प्लेटफॉर्म पर किया गया और इसमें शामिल सभी लोग सत्यापित नागरिक थे। सर्वे में भाग लेने के लिए लोकल सर्कल्स पर पंजीकरण जरूरी था।

बीएसएफ की नई रणनीति

भारत-बांग्लादेश सीमा पर किलेबंदी चिकन नेक में 12 फीट ऊंची फेंसिंग

नई दिल्ली » हिन्द शिला

पड़ोसी देश बांग्लादेश में जारी अशांति के बीच भारत–बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट है। इसी कड़ी में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चिकन नेक (सिलीगुड़ी कॉरिडोर) क्षेत्र में सीमा सुरक्षा को मजबूत करते हुए लगभग 75 प्रतिशत इलाके में नई डिजाइन की सीमा बाड़ (एनडीएफ) स्थापित कर दी है।

बीएसएफ अधिकारियों के मुताबिक 12 फीट ऊंची नई डिजाइन फेंसिंग को विशेष रूप से संवेदनशील इलाकों में लगाया गया है। इस बाड़ की खासियत यह है कि इसे काटने में कई मिनट लगते हैं और इसकी ऊंचाई व संरचना के कारण इसे पार करना भी बेहद मुश्किल है। अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था घुसपैठ की कोशिशों और मवेशी तस्करी जैसी घटनाओं में प्रभावी कमी लाने में मदद करेगी।

एक वरिष्ठ बीएसएफ अधिकारी ने बताया कि चिकन नेक क्षेत्र भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों की लाइफलाइन है, क्योंकि यही गलियारा शेष भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ता है। इसी कारण यहां तकनीक और मानव संसाधन- दोनों के जरिए सुरक्षा को अभूतपूर्व स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। नई फेंसिंग के साथ-साथ सीमा पर पैन-टिल्ट-जूम कैमरे लगाए गए हैं, जो रियल-टाइम लाइव फीड प्रदान करते हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करते हैं। बीएसएफ इसे 'स्मार्ट बॉर्डर' की दिशा में बड़ा कदम मान रहा है।अधिकारियों ने बताया कि एरिया डोमिनेशन प्लान में भी अहम बदलाव किए गए हैं। नए प्लान के तहत बीएसएफ उन इलाकों को निशाना बना रही है, जहां से मवेशियों को इकट्ठा कर सीमा के पास तस्करी के लिए लाया जाता है।

डायबिटीज कंट्रोल करने वाली दवा ही धीरे-धीरे और बढ़ा रही मर्ज!

नई दिल्ली » हिन्द शिला

डायबिटीज को शुगर की बीमारी कहा जाता है। इसमें शरीर में शुगर यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। यह दुनिया के साथ-साथ भारत में भी सबसे तेजी से बढ़ती बीमारियों में से एक है। टाइप 2 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिससे ब्लड शुगर बढ़ जाती है। इंसुलिन अग्न्याशय की बीटा कोशिकाएं बनाती हैं जो ब्लड शुगर कंट्रोल करती हैं। लेकिन हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना की रिसर्च में सामने आया है कि टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आमतौर पर जो दवा दी जाती है, वही दवा लंबे समय में टाइप 2 डायबिटीज को और भी बदतर कर सकती है।

डायबिटीज, ओबेसिटी एंड मेटाबोलिस्म में पब्लिश हुई रिसर्च के मुताबिक, टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में सल्फोनिल्यूरिया कैटेगरी की दवाएं जैसे ग्लिबेनक्लामाइड सालों से उपयोग की जा रही हैं। स्टडी के लीड प्रोफेसर एडुआर्ड मोंटान्या ने समझाया, 'टाइप 2 डायबिटीज में सालों से सल्फोनिल्यूरिया दवाएं दी जाती रही हैं जो बीटा कोशिकाओं को अधिक इंसुलिन रिलीज के लिए स्टिम्युलेट करती हैं।'

'ग्लिबेनक्लामाइड इन्हीं में से एक कॉमन दवा है जो कई देशों में जेनरिक फॉर्म में उपलब्ध है। लेकिन हमारी रिसर्च बताती है कि जब बीटा कोशिकाएं लंबे समय तक ऐसी दवा के संपर्क में रहती हैं तो उनकी सेहत और पहचान दोनों पर नेगेटिव असर पड़ सकता है।' प्रोफेसर मोंटाण्या के अनुसार, बीटा कोशिकाएं दवाओं के कारण मरती नहीं हैं बल्कि वे अपनी पहचान खो देती हैं। टेस्टिंग में पाया गया है कि ग्लिबेनक्लामाइड के लंबे समय तक प्रयोग से उनकी जीन एक्टिविटी कम हो जाती है जो इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं।'

ट्रम्प ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति को दी धमकी

अमेरिका की बात नहीं मानी तो मादुरो से भी बुरा हाल होगा

वॉशिंगटन » हिन्द शिला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को बुरा हाल करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा अगर डेल्सी वह नहीं करतीं जो वेनेजुएला के लिए अमेरिका सही मानता है, तो उनका हाल मादुरो से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। ट्रम्प ने यह बात एक इंटरव्यू में कही है। एक दिन पहले ट्रम्प ने कहा था कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रोड्रिग्ज से बात की है। वे वेनेजुएला में लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए अमेरिका की अपेक्षाओं पर काम करने को तैयार हैं। ट्रम्प ने कहा था अगर रोड्रिग्ज अमेरिका की बात मान लेती हैं तो वेनेजुएला में अमेरिकी सेना तैनात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं, रोड्रिग्ज ने मादुरो को सत्ता से हटाने की आलोचना की है। साथ ही अमेरिका से मादुरो को वापस भेजने की मांग की है। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को अंतरिम राष्ट्रपति बनाने का आदेश दिया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी रोड्रिग्ज को तुरंत राष्ट्रपति के सभी अधिकारों के साथ अंतरिम तौर पर कार्यभार संभालने के लिए कहा है।

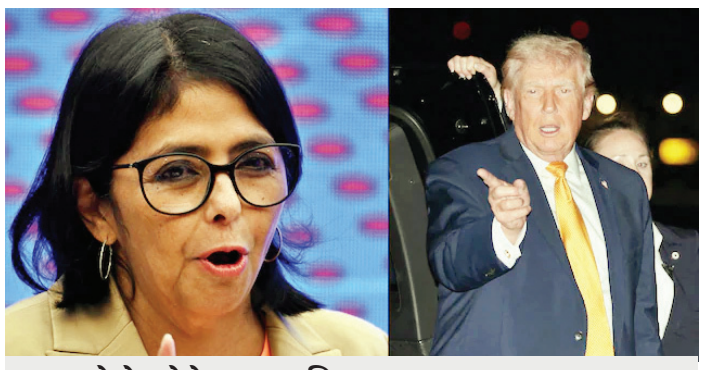

ट्रम्प बोले- वेनेजुएला की कमान अब अमेरिका के हाथ में

ट्रम्प ने कहा है कि इस समय वेनेजुएला की कमान अमेरिका के हाथ में है। रविवार रात एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में ट्रम्प ने बताया कि अमेरिका वेनेजुएला की नई लीडरशिप यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज से सीधे बातचीत कर रहा है। ट्रम्प ने बताया कि उन्होंने अभी तक डेल्सी रोड्रिग्ज से खुद बात नहीं की है, लेकिन उनके सहयोगियों ने संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि सही समय आने पर वे उनसे बात करेंगे। ट्रम्प ने यह भी दावा किया कि अमेरिका ने सहयोग के बदले रोड्रिग्ज को कुछ नहीं दिया, लेकिन वह सहयोग कर रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने एक साल अपील करने पर रोक लगाई

दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद-शरजील को नहीं मिली जमानत

नई दिल्ली » हिन्द शिला

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि 5 अन्य आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर और शरजील एक साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं।

दरअसल, उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद दिल्ली दंगों के आरोप में 5 साल 3 महीने से तिहाड़ में बंद थे। इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उन्हें गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत जमानत देने से इनकार किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, 'अनुच्छेद 21 संवैधानिक व्यवस्था में एक खास जगह रखता है। ट्रायल से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता। स्वतंत्रता से वंचित करना मनमाना नहीं होगा। यूएपीए एक खास कानून के तौर पर उन शर्तों के बारे में एक कानूनी फैसला दिखाता है जिनके आधार पर ट्रायल से पहले जमानत दी जा सकती है।

19 साल में 11वीं बार मां बनी हरियाणा की सुनीता

फतेहाबाद में 10 बेटियों के बाद हुआ बेटे का जन्म

फतेहाबाद » हिन्द शिला

हरियाणा के फतेहाबाद जिले के भूना ब्लॉक स्थित ढाणी भोजराज गांव में इन दिनों एक अनोखी खुशी की कहानी हर जुबान पर है। गांव के एक साधारण से परिवार में 19 साल के लंबे इंतजार के बाद बेटे का जन्म हुआ है। इस दंपती की इससे पहले 10 बेटियां हैं और 11वीं संतान के रूप में बेटे ने जन्म लिया है। ढाणी

भोजराज के रहने वाले संजय और उनकी पत्नी सुनीता की शादी को पूरे 19 साल हो चुके हैं।

शादी के शुरुआती सालों से ही उन्हें बेटे की चाह थी, लेकिन समय के साथ उनके घर एक-एक कर 10 बेटियों ने जन्म लिया। संजय का कहना है कि उन्होंने हमेशा अपनी बेटियों को बेटे के समान ही माना। लोग ताने देते थे, तरह-तरह की बातें कहते थे, लेकिन हमने कभी बेटियों को बोझ नहीं समझा। संजय बताते हैं। उनकी सबसे बड़ी बेटी 18 साल की है और 12वीं कक्षा में पढ़ रही है।

पाकिस्तान में पंजाबी महिला सरबजीत गिरफ्तार

नई दिल्ली » हिन्द शिला

सिख श्रद्धालुओं के साथ पंजाब से पाकिस्तान जाकर निकाह करने वाली पंजाबी महिला सरबजीत कौर को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया है। सरबजीत के साथ उसके पाकिस्तानी पति नासिर हुसैन को भी हिरासत में लिया गया है। सरबजीत को पाकिस्तान से अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत डिपोर्ट किया जाएगा। सरबजीत कौर 4 नवंबर 2025 को श्री गुरुनानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ पाकिस्तान गई थी। उसने वहां जाकर पाकिस्तानी व्यक्ति नासिर हुसैन से निकाह कर लिया था। निकाह के लिए सरबजीत ने मुस्लिम धर्म अपनाकर अपना नाम भी नूर हुसैन रख लिया था।

पाकिस्तान शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और पाकिस्तानी पंजाब सरकार के मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा ने सरबजीत की गिरफ्तारी की पुष्टि की। अरोड़ा ने कहा- 4 जनवरी 2026 को ननकाना साहिब के गांव पेहरे वाली में इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। पाकिस्तान सरकार ने सरबजीत को भारत डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का निर्णय

कैंसर की पहचान में एआई उपकरणों के लिए लाइसेंस जरूरी

नई दिल्ली » हिन्द शिला

कैंसर इलाज में तेजी से बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इस्तेमाल के बीच केंद्र सरकार ने मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सख्त फैसला लिया है। एआई आधारित कैंसर पहचान और निदान करने वाले सॉफ्टवेयर को सरकार ने हाई रिस्क श्रेणी में रखने की घोषणा की है। साथ ही स्पष्ट किया है कि ऐसे किसी भी सॉफ्टवेयर का उपयोग नियामकीय मंजूरी और लाइसेंस के बिना नहीं किया जा सकेगा।

हाई रिस्क श्रेणी का मतलब है कि कोई चिकित्सा उपकरण या एआई सॉफ्टवेयर जो मरीज की जान, इलाज के फैसलों या बीमारी की दिशा पर सीधा असर डाल सकता है। इसलिए उस पर सबसे सख्त निगरानी और नियम लागू होंगे। सोमवार को नई दिल्ली स्थित केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने कैंसर की निगरानी व इलाज से जुड़े उपकरणों की नई सूची जारी की है, जिसके तहत कैंसर से जुड़े एआई आधारित सॉफ्टवेयर को क्लास-सी (उच्च जोखिम) श्रेणी में शामिल किया है। अब ये सॉफ्टवेयर सामान्य डिजिटल टूल नहीं, बल्कि चिकित्सा उपकरण की तरह माने जाएंगे और उन पर वही सख्त नियम लागू होंगे जो अन्य उच्च जोखिम वाले चिकित्सा उपकरणों पर होते हैं।

नए नियमों के तहत अब ऐसे एआई सॉफ्टवेयर को बाजार में लाने या अस्पतालों में इस्तेमाल करने से पहले सीडीएससीओ से लाइसेंस लेना, क्लिनिकल वैलिडेशन और परफॉर्मेंस डेटा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, इस्तेमाल के बाद भी इनकी निरंतर निगरानी करनी होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जो एआई सॉफ्टवेयर एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई, पैथोलॉजी स्लाइड या अन्य कैंसर की पहचान करते हैं उन्हें अब क्लिनिकल डेटा, परफॉर्मेंस वैलिडेशन और नियामकीय अनुमति से गुजरना होगा।

सुरक्षित नवाचार के लिए लिया फैसला

चिकित्सा तकनीक क्षेत्र से जुड़े कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे स्टार्ट-अप्स पर नियामकीय दबाव बढ़ेगा लेकिन सरकार ने जारी सूची में साफ तौर पर कहा है कि यह फैसला नवाचार रोकने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षित नवाचार सुनिश्चित करने के लिए है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि एआई केवल डॉक्टर की सहायता करेगा, अंतिम चिकित्सकीय निर्णय डॉक्टर का ही रहेगा। सीडीएससीओ ने कहा है कि नई रिस्क क्लासिफिकेशन के जरिए सरकार ने यह संदेश दिया है कि डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में तकनीक के साथ-साथ सुरक्षा और जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है।

स्वात्वाधिकारी प्रकाशक एवं मुद्रक **संजीत सिंह बघेल** द्वारा कुसुम प्रिंटर्स प्रिंटिंग प्रेस ग्राम- कचनारावा, हदवरिया, वार्ड नंबर-08, तहसील-ओबरा, ब्लॉक थाना कोन, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश 231226 से प्रकाशित मो.9399747312,
संपादक **संजीत सिंह बघेल**, सह संपादकः **प्रांशु एवं मोहित बघेल**, समाचार पत्र से संबंधित सभी विवादों के निपटारे के लिए न्यायिक क्षेत्र सिवनी न्यायालय रहेगा।